Request for cancelling Government decision concerning transfer of head office of Bharat Wagon and Engineering Company Ltd. and giving it an independent company status

डा. कुमकुम राय (बिहार) : उपसभापति महोदय, भारत वैगन कम्पनी, बिहार का जब 1978 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था, तब से यह प्रगति करती रही। किन्तु 1987 में भारत भारी उद्योग निगम, कोलकाता में विलय करने के बाद से यह कम्पनी लगातार रुग्ण होती गई। भारत भारी उद्योग निगम, कोलकाता द्वारा लिए गए सारे निर्णय अव्यावहारिक होते हैं। उदाहरणार्थ, अभी भारत भारी उद्योग निगम के कार्यकारी अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक ने भारत वैगन के प्रबन्ध निदेशक को अपना कार्यालय मुजफ्फरपुर स्थानान्तरित करने को कहा है। प्रधान कार्यालय पटना में होने से मोकामा व मुजफ्फरपुर इकाई को सामान्य रूप से चलाया जा सकता है। इस निर्णय से मोकामा इकाई के कामगारों में काफी रोष व्याप्त है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। भारत भारी उद्योग निगम केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा वैगन निर्माण के मुख्य अवयवों के क्रय का जिम्मा लिया गया, जिसे कभी भी समय पर पूरा नहीं किया गया और जब भी पूरा किया गया, उसे ऊँचे दामों पर किया गया, जिससे भारत वैगन की उत्पादकता एवं आर्थिक स्थिति पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ा। वर्तमान रेल मंत्री ने भारत वैगन को फिर से चलाने के लिए 30 करोड़ रुपए बोगी बनाने के ऑर्डर के साथ दिए, किन्तु भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता ने इसका लाभ बिहार की इन दोनों इकाइयों को नहीं लेने दिया।

अतः भारत वैगन के प्रधान कार्यालय का पटना से मुजफ्फरपुर ले जाने का निर्णय तत्काल निरस्त कर भारत वैगन को भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता से अलग कर स्वतंत्र कम्पनी का रूप दिया जाए, जिससे बिहार की यह महत्वपूर्ण कम्पनी स्वावलम्बी हो सके। इससे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत सरकार के उपक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जारी किए गए निर्देश, जिसमें डिसेन्ट्रलाइजेशन और सिम्प्लिफिकेशन पर जोर दिया गया है, का समुचित पालन हो सकेगा। अतः भारी उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले में शीघ्र निर्णय लें।

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : सर, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

Need to encourage Non-Conventional Energy Sector in the country

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देना आज हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि लगभग समाप्ति के कगार पर हैं जब कि सरकार की प्राथमिकताओं में शायद यह क्षेत्र अंतिम है। इसलिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के बजट को छोटा हिस्सा मिलता है। शायद यही कारण है कि सोलर लालटेन जैसे ग्रामीणों के उपयोगी यंत्र पर सब्सिडी समाप्त कर दी गयी है जब कि यह अभी तक ठीक से गांव तक पहुंच भी न पाया था। इसी कारण सोलर लालटेन की बिक्री आधे से भी कम हो गयी है। लगभग सभी राज्यों की गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसियां धनाभाव में योजनाओं का संचालन, प्रचार एवं प्रसार अत्यंत धीमी गति से चला रही हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है। अगर हमें वर्ष 2020

तक विकसित देशों की पंक्ति में खड़े होना है तो गैर-पारंपरिक ऊर्जा के विकास एवं प्रचार-प्रसार को गति प्रदान करना ही होगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि विगत 10 वर्षों से गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आगामी वर्षों के लक्ष्य निर्धारित हों तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधन राज्य सरकारों को तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए राज्य सरकारों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाय।

महोदय, मेरा मानना है कि गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में असीमित संभावनाएं उपलब्ध हैं। मात्र सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के विकास एवं उपलब्ध संभावनाओं के दोहन से देश हित के लिए अनगिनत मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में वरदान साबित हो सकता है। धन्यवाद।

Concern over lowering of foodgrain procurement targets by the Government of India

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to mention about the lowering of foodgrain procurement targets by the Government.

Sir, I rise to draw the attention of this House to the reported lowering of foodgrain procurement targets by the Government. I call upon the Government to clarify the position and, if the media report is true, explain the rationale behind such a decision. It has been reported that the foodgrain procurement targets were lowered in accordance with the recommendations of the McKinsey Report which had recommended to the Food Corporation of India to curtail its expenditure by Rs.2,300 crores in two years. If it is so, then the Government may take this House into confidence with regard to the basis on which such a recommendation was made and accepted by the Government. It must be appreciated that the agriculture largely remains a non-remunerative and unpredictable vocation. A large part of the agricultural sector in our country still lacks market access on profitable terms. The procurement by Government and its allied agencies is, perhaps, the largest and the most significant marketing channel for the farmers to sell their products. In the absence of procurement by the Government and due to lack of sufficient post-harvest storage facilities, the farmers may have to undertake distress sale in open market. The prerogative for selling products in the open market or to the Government should rest with the farmers. Before leaving agriculture to the dynamics of open market, we have to first provide storage infrastructure and better